



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 ई0 (कार्तिक 02, 1931 शक सम्वत्)

[संख्या-43

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	417-422	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	317	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	—	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लघु सिचाई अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

08 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 1520/II-2009-02(10)/2005-श्री मुहम्मद उमर, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिचाई वृत्त, हल्द्वानी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिचाई तथा वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी (मुख्यालय) का अतिरिक्त कार्यभार शासन के अग्रिम आदेशों तक दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

एन0 एस0 नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 2391/VII-2-09/24-ख/2007

प्रेषक,

श्री पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 05 अक्टूबर, 2009

विषय : ईट मिट्टी पर रॉयल्टी (स्वामित्व) हेतु वार्षिक समाधान योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ईट मिट्टी पर रॉयल्टी (स्वामित्व) हेतु वार्षिक समाधान योजना को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रचलित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	गटों के पायों की संख्या	वार्षिक प्रस्तावित समाधान राशि (रु0 में)
01	15 पाये तक	60,000.00
02	16 पाये तक	61,800.00
03	17 पाये तक	63,600.00
04	18 पाये तक	65,400.00
05	19 पाये तक	67,200.00
06	20 पाये तक	69,000.00
07	21 पाये तक	70,800.00
08	22 पाये तक	72,600.00
09	23 पाये तक	74,400.00
10	24 पाये तक	76,200.00
11	25 पाये तक	78,000.00

क्रम संख्या	भट्टों के पायों की संख्या	वार्षिक प्रस्तावित समाधान राशि (रु0 में)
12	26 पाये तक	79,800.00
13	27 पाये तक	81,600.00
14	28 पाये तक	83,400.00
15	29 पाये तक	85,200.00
16	30 पाये तक	87,000.00
17	31 पाये तक	88,800.00
18	32 पाये तक	90,600.00
19	33 पाये तक	92,400.00
20	34 पाये तक	94,200.00
21	35 पाये तक	96,000.00
22	36 पाये तक	97,800.00
23	37 पाये तक	99,600.00
24	38 पाये तक	1,01,400.00
25	39 पाये तक	1,03,200.00
26	40 पाये तक*	1,05,000.00

*40 पाये से अधिक हेतु प्रति पाया रु0 1,800.00 की दर से।

शर्त :-

1. ईट मिट्टी की रायल्टी की समाधान योजना हेतु ईट भट्टा स्वामी खनन अनुज्ञा-पत्र, प्रार्थना-पत्र निर्धारित शुल्क रु0 400.00 तथा एक शपथ-पत्र संलग्न कर भट्टे के पायों की संख्या उल्लिखित करते हुए सूची में पाये हेतु उल्लिखित धनराशि कोषागार में जमा कर कोषागार की मूल प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
2. खनन अनुज्ञा-पत्र की प्राप्ति हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ ईट मिट्टी के उत्खनन की स्थल स्थिति का स्पष्ट विवरण यथा खसरा संख्या, क्षेत्रफल, ग्राम, तहसील, थाना आदि का विवरण उल्लिखित किया जायेगा तथा निजी भूमिधरों की सहमति प्रस्तुत किया जाये, परन्तु आवेदित स्थल के मानचित्र की स्थिति की प्रति संलग्न किये जाने की शर्त नियमावली, 2001 के नियम 52 (2) शिथिल रहेगी।
3. इस समाधान योजना को स्वीकार करने वाले प्रार्थना-पत्र अथवा शपथ-पत्र में उल्लिखित पायों की संख्या की जांच सक्षम अधिकारी (ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) करेंगे। यदि जांच में प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित पायों की संख्या से अधिक पायों की संख्या पायी जाती है तब समाधान योजना के प्रस्तावों को अस्वीकृत समझा जायेगा तथा भट्टा स्वामी की वास्तविक उत्पादित ईटों पर तत्समय प्रचलित ईटों पर रॉयल्टी की धनराशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा विनिश्चित रॉयल्टी की धनराशि ऐसे भट्टा स्वामी पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।
4. ईट भट्टा स्वामी ईट भट्टे का स्थान एवं पायों की संख्या में परिवर्तन की दशा में परिवर्तन की सूचना 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से सम्बन्धित कार्यालय को देनी होगी तथा ऐसा करने में विफल रहने पर समाधान योजना की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
5. ईट भट्टा स्वामी उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली, 2001 के अन्तर्गत उल्लिखित निर्बन्धन एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होंगे।
6. ईट भट्टों पर पायों की संख्या के अतिरिक्त गढ़दों की नाप कर उत्पादित ईटों का आकलन नहीं किया जायेगा।
7. जिलाधिकारी द्वारा प्रपत्र एम0एम0-10 पर एक माह में खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जायेगा।
8. जनपद में निर्गत किये गये खनन अनुज्ञा-पत्र की मद में जमा धनराशि का मासिक विवरण आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करायें।

9. जनपद में कार्यरत भट्टों की प्रमाणित सूचना प्राप्त करने हेतु जनपद के व्यापार कर विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ईट भट्टों की सूची तथा तहसील के माध्यम से लेखपालों की पड़ताल के आधार पर प्राप्त सूची का मिलान कर वास्तविक कार्यरत भट्टों की पायों की संख्या सहित पहचान की जाय, कार्यरत वास्तविक भट्टों की पहचान हो जाने पर खनन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न करने वाले ईट भट्टों से नियमानुसार रायल्टी वसूली हेतु कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0 सी0 शर्मा,

प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

13 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 598/2009/XXVII(8)/सू0अ0अ0/05-“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” (2005 का अधिनियम संख्या-22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के मण्डलीय स्तर (संभागीय स्तर) हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाईयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मण्डलीय स्तर (संभागीय स्तर)

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	देहरादून संभाग	असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तरकाशी	संबंधित कार्यालय/खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून
2.	हरिद्वार संभाग	डिप्टी कमिशनर (क0नि0) वाणिज्य कर, कोटद्वार	संबंधित कार्यालय/खण्ड के असिस्टेन्ट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार
3.	हरिद्वार संभाग	असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, श्रीनगर	संबंधित कार्यालय/खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार
4.	हरिद्वार संभाग	असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, गोपेश्वर	संबंधित कार्यालय/खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार
5.	काशीपुर संभाग	असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, किच्छा	संबंधित कार्यालय/खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग, काशीपुर
6.	नैनीताल संभाग	असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, बागेश्वर	संबंधित कार्यालय/खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी	ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक), नैनीताल संभाग, हल्द्वानी

2-अधिसूचना सं0-1227/XXVII(5)/व्या0कर/2005, दि0 13-10-2005 में मण्डलीय स्तर (संभागीय स्तर) के क्रम संख्या-4 के अपीलीय अधिकारी के कॉलम 5 में अंकित "ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) काशीपुर" के स्थान पर "ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), नैनीताल संभाग, हल्द्वानी" पढ़ा जाये।

3-शासन की पूर्व अधिसूचना संख्या-1227/XXVII(5)/व्या0कर/2005, दि0 13-10-2005 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, अधिसूचना की शेष शर्तें एवं अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग-1

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

13 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 1956/XXX-1-09-18(15)/2002 T.C. उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों का अन्तिम आवंटन, मा0 न्यायालयों में लग्गित याचिकाओं के कारण प्रभावी न होने के कारण डिप्टी कलेक्टर के पद की अस्थायी रिक्तियां विद्यमान हैं। अतः डिप्टी कलेक्टर के पद पर अस्थायी रिक्तियां उपलब्ध होने के कारण निम्नलिखित तहसीलदार को शासकीय कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा जनहित में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिप्टी कलेक्टर के पद वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पूर्व वेतनमान रु0 8,000-13,500) में एक वर्ष के लिए अथवा सीधी भर्ती के अधिकारी तैनाती हेतु उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	नाम अधिकारी	तैनाती का स्थान
01	श्री रामदत्त	डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़

2-उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई है और नितांत काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी है जो किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त अधिकारी प्रत्यावर्तन पर किसी क्षतिपूर्ति के अधिकारी नहीं होंगे।

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग-3

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2009 ई0

संख्या 889/XXVIII-3-2009-133/2007-राज्यपाल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, सन् 1954) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से श्री डी0के0 शर्मा, लोक विश्लेषक, कम्पोजिट परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को उत्तराखण्ड राज्य के खाद्य श्रेणी के समस्त वस्तुओं के विश्लेषण हेतु लोक विश्लेषक नियुक्त करते हैं।

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर, 2009 ई०

संख्या 1428/VIII/544-ई०एस०आई०/2005-चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 34, वर्ष 1948) के अधीन उपबन्धित लाभों से उच्चतर लाभ प्राप्त है;

2-अतएव, उक्त अधिनियम की धारा, 90 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 1458/36-7-97-5(39)/96, लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई, 1998 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा० दिलबाग सिंह,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 ई0 (कार्तिक 02, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 25, 2009

No. 186/UHC/XIV/62/Admin.A--Sri Amit Kumar Sirohi, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 07.09.2009 to 15.09.2009.

October 06, 2009

No. 187/XIV/39/Admin.A/2008--Sri Laxman Singh, Judicial Magistrate, Rudrapur is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 26.08.2009 to 19.09.2009 with permission to suffix 20.09.2009 as Sunday and 21.09.2009 as Id-ul-Fitr holiday.

October 07, 2009

No. 188/XIV/40/Admin.A/2008--Smt. Deepali Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 08.09.2009 to 11.09.2009.

October 09, 2009

No. 190/UHC/XIV/57/Admin.A--Sri Ajay Chaudhary, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 30.07.2009 to 07.08.2009 with permission to suffix 08.08.2009 as 2nd Saturday.

October 13, 2009

No. 193/UHC/XIV-93/Admin.A--Sri Sanjeev Kumar, the then Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar Distt. Pauri Garhwal, presently posted as 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 29.06.2009 to 03.07.2009 with permission to prefix 28.06.2009 as Sunday.

October 14, 2009

No. 194/UHC/XIV/71/Admin.A--Smt. Neena Agarwal, the then 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, presently posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 21.08.2009 to 04.09.2009.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/477-भाग 1-क-2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।